उत्तराखण्ड शासन

कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका

2024-25

ITDA

सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

प्राक्कथन

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवायें सरलता पूर्वक उपलब्ध कराने, विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का सफल उपयोग सुनिश्चित करने तथा समाज के विभिन्न अवयवों को उनकी आवश्यकता अनुसार सूचना सुलभ कराने के लिए उच्चस्तरीय निर्णय के अन्तर्गत शासन स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का गठन उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के उपरान्त किया गया है। वर्ष 2002–03 के उपरान्त प्रत्येक वर्ष विभागीय वार्षिक योजना तैयार की जाती रही है। इस प्रकार विगत बाईस वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं को राज्य में सफलता पूर्वक लागू किया है।

राज्य में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 लागू की गयी, जिसका वर्तमान समय में सेवा सेक्टर नीति के अनुसार अद्यतिकरण किया जा रहा है। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक संचार के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार की Right of Way Policy को राज्य हेतु भी अपना लिया गया, इस नीति में राज्य में संचार व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने, मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। राज्य के नागरिकों को साईबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से Cyber Crisis Managerment Plan (CCMP) एवं Critical Information Infrastructure (CII) Guideline का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य में स्टेट डाटा सेंटर का क्रियान्वयन किया जा चुका है एवं डाटा सेंटर पोलिसी भी जारी की जा चुकी है। ड्रोन के बढ़ते उपयोग के चलते राज्य में ड्रोन संचालन एवं निर्माण हेतु उत्तराखंड ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2023 जारी की गयी है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विभिन्न अवस्थापना परियोजनायें यथा राज्यव्यापी नेटवर्क (स्वान) तथा स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है।

'अपणि सरकार पोर्टल' को सुदृढ़ करते हुए, डी.बी.टी. सहित 768 सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए ऑनलाईन माध्यम (वेबपोर्टल और मोबाईल एप्लिकेशन) से उपलब्ध कराया गया। यह नागरिकों को सरकारी सेवायें प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अतिरिक्त राजकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के उद्देश्य से कार्यालयों एवं संस्थाओं में ई–ऑफिस का क्रियान्वयन कर कार्यालय कार्यों को डिजिटल माध्यम से सम्पादन किये जानी की कार्यवाही की जा रही है।

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	मुख्य उद्देश्य– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1
2.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अवयव	2
3.	अध्याय 1 : नीतियां/ दिशानिर्देश	4
4.	अध्याय 2 : सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना	6
5.	अध्याय 3 : सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवायें एवं सुशासन	9
6.	अध्याय 4 : क्षमता विकास एवं अनुसंधान कार्य	32
7.	अध्याय 5 : वित्तीय वर्ष 2023–24 वित्तीय प्रगति एवं 2024–25 आय–व्ययक अनुमान	35
8.	आउटकम /परफोरमेंस बजट 2024–25	36

मुख्य उद्देश्य– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने मूलतः निम्न मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया हैः–

1. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं क्रियान्वयन का प्रयास करना, जिससे कि विभागीय कार्यप्रणाली में वॉछित सुधार किया जा सके।
2. राष्ट्रीय ई–शासन प्लान (NeGP) का राज्य में क्रियान्वयन एवं उसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का राज्य के अनुरूप विकास एवं संचालन करने की दिशा में प्रयास।
3. राज्य के जिन विभागों द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध करायी जाती है, उनका कम्प्यूटरीकरण करना, जिससे नागरिकों को सरलतापूर्वक सुविधायें/ सेवायें प्राप्त हो सके।
4. विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का सुव्यवस्थित एकत्रीकरण एवं भण्डारण जिससे उन्हें विभिन्न उपयोगकर्ता–समूहों को उपलब्ध कराया जा सके।
5. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार करना, जिससे कि विभिन्न सामाजिक समूह उसका लाभ उठा सके, और राज्य सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थान प्राप्त कर सके।
6. सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी विभिन्न कार्यशालायें/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराना, जिससे राज्य के युवा–वर्ग को स्वरोजगार उपलब्ध हो सके।
7. सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अग्रणी विश्वस्तरीय कम्पनियों एवं संस्थाओं को राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने हेतु आकर्षित करना।
8. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर नागरिक सुविधाएं, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सामाजिक क्षेत्र में लाभ तथा रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रयास।
9. ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत शासकीय कार्यों में त्वरित कार्यवाही, पारदर्शिता, कार्यक्षमता एवं दक्षता में सुधार, स्वविवेक तथा पूर्वाग्रह से मुक्त कार्यप्रणाली तैयार करना।
10. ई–शासन के प्रति राजकीय कर्मचारियों तथा जन प्रतिनिधियों में जागरूकता बढ़ाना।
11. राज्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन हेतु प्लान का विकास करना व साईबर क्षेत्र में साईबर सुरक्षा आदि पर कार्यवाही।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अवयव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का ढांचा – शासन स्तर पर सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), द्वारा विभाग का मार्गदर्शन किया जा रहा है। सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) को सहयोगी सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव तथा सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग कार्यरत है।

सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी

विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में क्षेत्रीय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के रूप में एक संस्था गठित है, जो वर्ष 2004–05 में परियोजना प्रबन्धन इकाई, ई–गवर्नेन्स के रूप में गठित की गई थी। यह संस्था सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई–गवर्नेन्स परियोजना हेतु राज्य की नोडल संस्था नामित है। आई.टी.डी.ए. के संशोधित ढांचे के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद
1.	अध्यक्ष (पदेन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन)	1
2.	उपाध्यक्ष (पदेन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी उत्तराखण्ड शासन)	1
3.	निदेशक	1
4.	अपर निदेशक (प्रशासन)	1
5.	वित्त नियंत्रक (वित्त एवं प्रोक्योरमेंट)	1
6.	महाप्रबन्धक (सूचना प्रौद्योगिकी)	1
7.	उपमहाप्रबन्धक (सूचना प्रौद्योगिकी अवस्थापना)	1
8.	उपमहाप्रबन्धक (सेवायें)	1
9.	उपमहाप्रबन्धक (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट)	1
10.	वरिष्ठ कार्यकारी (सूचना प्रौद्योगिकी अवस्थापना)	1
11.	वरिष्ठ कार्यकारी (स्वान अवस्थापना)	1
12.	वरिष्ठ कार्यकारी (ई–सेवायें)	2
13.	वरिष्ठ कार्यकारी (साईबर सुरक्षा)	1
14.	वरिष्ठ कार्यकारी (आई.टी. सुधार/ ईमर्जिंग टेकनोलॉजी)	1
15.	वरिष्ठ कार्यकारी (जी.आई.एस. एवं ड्रोन अनुसंधान केन्द्र)	1

16.	वरिष्ठ कार्यकारी (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली)	1
17.	वरिष्ठ कार्यकारी (CALC)	1
18.	प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	1
19.	प्रबन्धक (अनुबन्ध प्रबन्धन एवं अधिप्राप्ति)	1
20.	कार्यालय अधीक्षक	1
21.	लोक सम्पर्क अधिकारी	1
22.	सलाहकार (एकाउन्ट – ऑडिटर)	1
23.	वैयक्तिक सहायक	2
24.	परियोजना सहायक	10
25.	मल्टीपर्पज स्टाफ	8
26.	गार्ड	6

उपरोक्त के अतिरिक्त सी0एम0 हैल्पलाईन '1905' के संचालन हेतु निम्नलिखित पद स्वीकृत हैं, तथा सम्बन्धित कॉल सेंटर के संचालन हेतु सेवायें आउटसोर्स की गयी हैं–

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद
1.	प्रबन्धक सामान्य प्रशासन/ जी.पी.आर.	1
2.	प्रबन्धक हैल्पलाईन	1
3.	सॉफ्टवेयर डेवलपर	3
4.	सिस्टम एनेलिस्ट	1
5.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	3
6.	मल्टीपरपज वर्कर (सहायक)	2

इसके अतिरिक्त आई.टी.डी.ए. के अन्तर्गत संचालित अन्य परियोजनाओं यथा–स्टेट डाटा सेंटर, क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान), ड्रोन, आई.टी.डी.ए. कैल्क, ई–ऑफिस, अपणि सरकार, ई–गवर्नेन्स सेवाओं हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से तकनीकी मानव संसाधन आबद्ध किये गये हैं।

अध्याय 1

नीतियां / दिशानिर्देश

सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य को पूर्ण रूप से डिजिटलीकृत तथा नेटवर्क आधारित समाज की परिकल्पना को पूर्ण करने, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं को प्रोत्साहित कर इलनेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजायन तथा विर्निमाण उद्योग में निवेश को आकर्षित कर राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 जारी की गयी है।

Right of Way Policy 2018

यह नीति वर्ष 2018 में जारी की गयी थी तथा वर्तमान में राज्य के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय Right of Way नीति को अपनाया गया है। इस नीति में राज्य में संचार हेतु ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने, मोबाईल टावर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

साईबर सुरक्षा हेतु नीति एवं दिशानिर्देश

राज्य के आई0टी0 (Information Technology) अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु तथा साथ ही राज्य के नागरिकों को साईबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से Cyber Crisis Management Plan (CCMP) एवं Critical Information Infrastructure (CII) Guideline का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में Sectoral Cert एवं सचिव, सूचना प्रौद्यौगिकी की अध्यक्षता में Cert-UTK समिति गठित की गयी है। उक्त प्लान एवं नीतियों को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा नागरिकोन्मुख सेवाओं की प्रभावी एवं पारदर्शी सर्विस डिलीवरी हेतु माननीय मुख्यमंत्री

जी की अध्यक्षता में **उत्तराखण्ड राज्य सुशासन परिषद** तथा मुख्यसचिव की अध्यक्षता में **उच्चाधिकार प्राप्त समिति** का गठन किया गया है।

ई–वेस्ट पोलिसी

राजकीय विभागों में कम्प्यूटर के बढ़ते उपयोग के दृष्टिगत निकट भविष्य में ई–कचर की बढ़ती हुई मात्रा का निस्तारण किया जाना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य के लिए ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम 2023 जारी किये गये हैं।

ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2023

वर्तमान में ड्रोन के बढ़ते उपयोग के चलते राज्य में ड्रोन संचालन एवं निर्माण हेतु उत्तराखंड ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2023 जारी की गयी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में ड्रोन के क्षेत्र में विनिर्माण निवेश को आकर्षित कर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा ड्रोन के उपोग को बढ़ावा देना भी नीति के उद्देश्य में सम्मिलित है।

अध्याय 2
सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना

भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना विकसित किये जाने हेतु विभिन्न परियोजनायें यथा– क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान), स्टेट डाटा सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर इत्यादि क्रियान्वित की गयी हैं, जिनका संचालन वर्तमान में किया जा रहा है।

नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान का उद्‌देश्य था कि कि राज्यों के लिए राज्य डाटा केन्द्रों की शुरूआत कर सेवाओं, अनुप्रयोगों तथा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए G2G (सरकार से सरकार), G2C (सरकार से नागरिक) एवं G2B (सरकार से व्यापार) सेवायें प्रभावी इलेक्ट्रानिक रूप में आपूर्ति की जा सके। इन सेवाओं को सामान्य आपूर्ति प्लेटफार्म के माध्यम से सुलभ कराया जा सकता है तथा राज्यव्यापी क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) एवं सामान्य सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) जैसे केन्द्रीय सम्पर्क अवसंरचना के सहयोग से ग्राम स्तर तक सम्पर्क को बढ़ाया जा सकता है।

क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान)

क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन भारत सरकार की नेशनल ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत एन0आई0सी0 के माध्यम से वर्ष 2010 में पूर्ण की गयी थी तथा वर्ष 2015 में परियोजना राज्य सरकार को हस्तान्तरित होने के उपरान्त से आई0टी0डी0ए0 द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आई0टी0डी0ए0 द्वारा परियोजना हस्तान्तरण के उपरान्त समस्त स्वान केन्द्रों पर अत्याधुनिक नेटवर्क उपकरणों को स्थापित कर 139 प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स (POP) के माध्यम से संचालन किया जा रहा है। स्वान संचालन केन्द्र (Network Operation Center) सूचना प्रौद्योगिकी भवन (आई0टी0डी0ए0) में स्थापित है। स्वान के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय तथा तहसील/ ब्लॉक मुख्यालय तक बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है। स्वान को जनपद स्तर पर नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एन0के0एन0) से सयोंजित किया गया है, प्रत्येक स्वान केन्द्र मे बी0एस0एन0एल0, एन0के0एन0 तथा एयरटेल के माध्यम से बैंडविड्थ प्रदान की जा रही है। इसमें जिला मुख्यालय तक 100/250/ 500/ 1024 एम0बी0पी0एस0 तक बैंडविड्थ उपलब्ध हो रही है, तथा ब्लॉक/ तहसील स्तर तक 10/34/100/300 एम.बी.पी.

एस. बैडविड्थ प्रदान की जा रही है। नेटवर्क के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु प्रत्येक POP पर नेटवर्क इंजीनियर्स तैनात हैं।

समस्त स्वान केन्द्रों पर नेटवर्क उपकरणों का अपग्रेडेशन कार्य पूर्ण कर एस0डी0वैन0 उपकरणो को स्थापित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी भवन (आई0टी0डी0ए0) से विधान सभा, सचिवालय होते हुए सूचना प्रौद्योगिकी भवन (आई0टी0डी0ए0) तक रिंग–कनेक्टिविटी के माध्यम से 40 विभागो की कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है। वर्तमान में स्वान नेटवर्क के अन्तर्गत राज्य के 13 जनपदों में स्थापित राजकीय विभागों के 2012 कार्यालय संयोजित किये गये है, जिसमें मुख्यतः जिलाधिकारी, समस्त कोषागार, जी0एस0टी0 कार्यालय, आर0टी0ओ0 कार्यालय, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जिला आपूर्ति कार्यालय इत्यादि सम्मिलित हैं। स्वान नेटवर्क द्वारा (Voice, data & Video) इंटरनेट एवं विडियो कांफ्रेसिंग की सुविधायें ब्लॉक/ तहसील स्तर तक उपलब्ध करायी जा रही है।

स्टेट डाटा सेंटर

भारत सरकार की नेशनल ई–गवर्नेस योजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी भवन, आई.टी. पार्क में उत्तराखण्ड स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना वर्ष 2018 में की गयी। जिसका उद्देश्य राज्य के समस्त विभागों के एप्लीकेशन/वेबासईट को डाटा सेन्टर में होस्ट करना है।

स्टेट डाटा सेन्टर मे वर्तमान में लगभग 99 विभागों की 167 एप्लिकेशन होस्ट कर लाईव की जा चुकी हैं। राज्य के विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत आगामी वर्षों में डाटा सेंटर का विस्तारीकरण एवं डाटा सेंटर हेतु डिजास्टर रिकवरी का प्रवधान किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

सामान्य सेवा केन्द्र 'देवभूमि जन सेवा केन्द्र'

भारत सरकार द्वारा नेशनल ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना का स्वीकृत की गयी थी। इसके अन्तर्गत समेकित रूप से ग्रामीण जनता को सरकार, निजी एवं सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख सेवाओं के लिए शुरू से अंत तक डिलीवरी सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफार्म विकसित करना है, जो सूचना आधारित तथा गैर–सूचना आधारित सेवाओं के संयोजन से देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के लाभ के लिए अपने

सामाजिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए सरकार, निजी तथा सामाजिक क्षेत्र के संगठनों को समर्थ बना सके।

वर्तमान में 24100 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत हैं, जिनमें से 19003 कॉमन सर्विस सेंटर ग्राम पंचायतों में स्थापित हैं। 9461 सी.एस.सी. ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत किये गये हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ई–डिस्ट्रिक्ट एवं राज्य तथा केन्द्र की अन्य G2C सेवायें प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त सी. एस.सी. के माध्यम से विभिन्न B2C सेवायें भी प्रदान की जा रही है।

सी0एस0सी0 के माध्यम से अपणि सरकार की 228 सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त देहरादून नगर दिगम (पायलट प्रोजेक्ट) के 100 वार्ड में **Door step Delivery** के माध्यम से अपणि सरकार की सेवाएं नागरिकों को उनके निवास पर प्रदान की जा रही है।

'लास्ट माईल कनेक्टिविटी'

भारत सरकार से विशेष सहायता के अन्तर्गत 2022–23 में रुपये 50 करोड़ की धनराशि उत्तराखण्ड राज्य में भारत नेट फेज–1 की समस्त ग्राम पंचायतों तक एफ.टी.टी.एच. कनेक्टिविटी स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृत की गयी।

उपरोक्त कनेक्टिविटी भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से दो चरणों में किये जाने का निर्णय लिया गया था। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के 966 ग्राम पंचायतों में फिजिबल 3090 स्थलों में कनेक्टिविटी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं द्वितीय चरण में कुल 3500 स्थलों मे कनेक्टिविटी के सापेक्ष भारत संचार निगम लि. द्वारा 21 ग्राम पंचायतों के 479 स्थलों में कनेक्टिविटी पूर्ण कर दी गयी है।

आई0टी0 पार्क में आई0टी0डी0ए0 को अतिरिक्त भूमि आवंटन

आई0टी0 पार्क देहरादून में सिडकुल द्वारा आई0टी0डी0ए0 को 2000 वर्ग मीटर का अतिरिक्त भूखण्ड आवंटित किया गया है। ब्रिडकुल को शासन द्वारा कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त निर्माण हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0 रुपये 36.70 करोड़ के सापेक्ष ब्रिडकुल को 21.34 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। निर्माणाधीन भवन में नये उच्च क्षमता वाले डाटा सेंटर, साईबर सिक्योरिटी हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, ड्रोन इनोवेशन लैब की स्थापना, आई0टी0 इन्कुबेशन फैसिलिटी, ई–वेस्ट हैंडलिंग फैसिलिटी, कार्यशालाओं इत्यादि हेतु ओडिटोरियम की स्थापना आदि का संचालन प्रस्तावित है।

अध्याय 3

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवायें एवं सुशासन

''अपणि सरकार पोर्टल''

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी विभागों की नागरिक सेवाओं को एकीकृत करते हुए जनमानस तक सुविधाजनक, कुशल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ''अपणि सरकार'' पोर्टल की शुरूआत की गयी है। यह जीरो टॉलेरेन्स ऑन करपशन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रतिबिम्ब है।

''अपणि सरकार पोर्टल'' के माध्यम से विभिन्न 73 विभागों की 768 नागरिक केन्द्रित सेवाओं को विकसित एवं एकीककृत करते हुए "Faceless, Paperless एवं Cashless" तरीके से आम नागरिकों को उपलब्ध करायी जा रही है। यह सेवाएं नागरिकों को ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों, सी0एस0सी0 केन्द्रों एवं वेबपोर्टल तथा मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा रही है।

अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही नागरिक सेवाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
1	केदारनाथी के लिए हेली सेवाएं	यूकाडा
2	औली रोपवे ऑनलाइन बुक करें	
3	औली चेयर लिफ्ट कार ऑनलाइन बुक करें	
4	आधार की स्तिथि जाँचे	यूआईडीएआई
5	आधार अपडेट करें	
6	अपॉइंटमेंट बुक करें	
7	ईमेल/मोबाइल नंबर सत्यापित करें	
8	आधार सत्यापित करें	
9	डाउनलोड आधार	
10	शिकायत दर्ज करें	
11	औषधि वितरण हेतु नवीन लाइसेंस निर्गत करना	खाद्य एवं औषधि प्रशासन
12	औषधि वितरण हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण करना	
13	औषधि निर्माण हेतु नवीन लाइसेंस निर्गत करना	
14	औषधि निर्माण हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण करना	
15	खाद्य लाइसेंस का नवीनीकरण	
16	खाद्य लाइसेंस निर्गत का पंजीकरण	
17	एनएफएसए के राशन कार्ड का आवेदन/नवीनीकरण/संशोधन/निपटान/स्थानांतरण	खाद्य और नागरिक आपूर्ति
18	राज्य खाद्य योजना के राशन कार्ड आवेदन/नवीनीकरण/संशोधन/ निपटान/ स्थानांतरण	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
19	राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले राज्य के खिलाड़ी को नगद पुरस्कार हेतु आवेदन	खेल विभाग
20	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले राज्य के खिलाड़ी को नगद पुरस्कार हेतु आवेदन	
21	देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार पुरस्कार हेतु आवेदन	
22	देवभूमि उत्तराखण्ड हिमालय रत्न खेल पुरस्कार हेतु आवेदन	
23	देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु आवेदन	
24	बुकिंग पूजा–श्री बद्रीनाथ धाम	बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति
25	बुकिंग पूजा–श्री केदारनाथ धाम	
26	बुकिंग पूजा–श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ	
27	बुकिंग पूजा–श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ	
28	बद्रीनाथ मंदिर को ऑनलाइन दान	
29	केदारनाथ मंदिर को ऑनलाइन दान	
30	ऑनलाइन दान श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ	
31	ऑनलाइन दान–श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ	
32	आई.टी.आई. छात्रों के लिए चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति (28 दिनों तक) हेतु आवेदन	कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग
33	आई.टी.आई. छात्रों के लिए चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति (28 दिनों से अधिक) हेतु आवेदन)	
34	उत्तीर्ण परीक्षा परिणाम के साथ चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना (SCVT)	
35	स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन (SCVT)	
36	डुप्लीकेट अंक पत्र जारी करने हेतु आवेदन (SCVT)	
37	डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन (SCVT)	
38	अंकों की संवीक्षा के लिए आवेदन (SCVT)	
39	उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों की कौशनमनी की वापसी हेतु आवेदन	
40	उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन (SCVT)	
41	आवेदक द्वारा औपचारिकता पूर्ण करने पर संशोधित अंक पत्र जारी करना (SCVT)	
42	संसोधित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन (SCVT)	
43	आई.टी.आई. में प्रवेशित छात्रों के लिए अंक पत्र व प्रमाण पत्र की सत्यापन पश्चात वापसी	
44	मत्स्य पालन कार्ड के लिए आवेदन पत्र	मत्स्य विभाग
45	तालाब निर्माण/नवीनीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति	
46	तालाब निर्माण के बाद इनपुट की उपलब्धता	
47	मछली बीज वितरण	
48	मत्स्य आहार वितरण	
49	मत्स्य पालन के लिए तालाब पट्टे के आवंटन के बाद इनपुट/भुगतान सहायता	
50	एंगलिंग	
51	व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना	कृषि विभाग
52	कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना	
53	थोक व्यापार के लिए लाइसेन्स निर्गत हेतु	
54	थोक व्यापार हेतु लाइसेन्स नवीनीकरण	
55	छात्रवृत्ति योजना	
56	थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता के लिए बिक्री/भंडारण के लिए आवेदन में संशोधन (उर्वरक के तहत सेवाएं)	
57	उर्वरक राज्य प्रकोष्ठ सी और एफ के लिए प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन में संशोधन; उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत	
58	कीटनाशकों के निर्माण के लिए अनुदान लाइसेंस हेतु आवेदन में संशोधन	
59	बीजों के विक्रय एवं भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन में संशोधन	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
60	उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत मिश्रण/विशेष मिश्रण उर्वरक के निर्माण के लिए प्रमाणपत्र में संशोधन	
61	कीटनाशकों को बेचने, स्टॉक करने या प्रदर्शन करने या वितरित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन में संशोधन	
62	उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत मिश्रण/विशेष मिश्रण उर्वरक के निर्माण के लिए प्रमाण पत्र	
63	थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता के लिए बिक्री/भंडारण हेतु आवेदन (उर्वरक के अंतर्गत सेवा)	
64	उर्वरक राज्य प्रकोष्ठ सी एंड एफ के लिए प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत	
65	उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित उत्पाद के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	
66	कीटनाशक वाणिज्यिक कीट नियंत्रण कार्यों के स्टॉक और उपयोग के लिए अनुदान लाइसेंस के लिए आवेदन	
67	कीटनाशकों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन	
68	बीजों के विक्रय एवं भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन	
69	कीटनाशकों को बेचने, स्टॉक करने या बेचने या वितरित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन	
70	थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता के लिए बिक्री/भंडारण के लिए आवेदन का नवीनीकरण (उर्वरक के तहत सेवा)	
71	उर्वरक राज्य प्रकोष्ठ सी एंड एफ के लिए प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन का नवीनीकरण एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत	
72	कीटनाशक वाणिज्यिक कीट नियंत्रण कार्यों के स्टॉक और उपयोग के लिए अनुदान लाइसेंस के लिए आवेदन का नवीनीकरण	
73	बीज के विक्रय एवं भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र का नवीनीकरण	
74	उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत मिश्रण/विशेष मिश्रण उर्वरक के निर्माण के लिए प्रमाणपत्र का नवीनीकरण	
75	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	कृषि और किसान कल्याण विभाग
76	किसान लॉगिन	
77	पंजीकरण	
78	फसल हानि की रिपोर्ट करें	
79	आवेदन की स्थिति	
80	तकनीकी शिकायत	
81	इंटरमीडिएट (कक्षा 12 वीं) के लिए मूल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन	विद्यालयी शिक्षा
82	हाई स्कूल (कक्षा 10 वीं) के लिए मूल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन	
83	इंटरमीडिएट (कक्षा 12 वीं) के लिए मूल अंक पत्र जारी करने के लिए आवेदन	
84	हाई स्कूल (कक्षा 10 वीं) के लिए मूल अंक पत्र जारी करने के लिए आवेदन	
85	इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के लिए डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन	
86	हाई स्कूल (कक्षा 10 वीं) के लिए डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन	
87	इंटरमीडिएट (कक्षा 12 वीं) के लिए डुप्लीकेट अंक पत्र जारी करने के लिए आवेदन	
88	हाई स्कूल (कक्षा 10 वीं) के लिए डुप्लीकेट अंक पत्र जारी करने के लिए आवेदन	
89	इंटरमीडिएट (कक्षा 12 वीं) के लिए प्रमाण पत्र में सुधार के लिए आवेदन	
90	हाई स्कूल (कक्षा 10 वीं) के प्रमाण पत्र में सुधार के लिए आवेदन	
91	इंटरमीडिएट (कक्षा 12 वीं) के लिए अंक पत्र में सुधार के लिए आवेदन	
92	हाई स्कूल (कक्षा 10 वीं) के लिए अंक पत्र में सुधार के लिए आवेदन	
93	माइग्रेशन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन (कक्षा 12वीं)	
94	इंटरमीडिएट (कक्षा 12 वीं) के लिए स्थानांतरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
95	हाई स्कूल (कक्षा 10 वीं) के लिए स्थानांतरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन	
96	इंटरमीडिएट (कक्षा 12 वीं) के लिए रद्द परीक्षा पर निर्णय के लिए आवेदन	
97	हाई स्कूल (कक्षा 10 वीं) के लिए रद्द परीक्षा पर निर्णय के लिए आवेदन	
98	इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के अपूर्ण/गलत परिणाम में सुधार के लिए आवेदन	
99	हाई स्कूल (कक्षा 10 वीं) के लिए अपूर्ण/गलत परिणाम में सुधार के लिए आवेदन	
100	इंटरमीडिएट (कक्षा 12 वीं) के लिए रोक परिणाम पर र्निणय के लिए आवेदन	
101	हाई स्कूल (कक्षा 10 वीं) के लिए रोक परिणाम पर र्निणय के लिए आवेदन	
102	आरटीई के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन	
103	छात्रावास निर्माण की स्वीकृति	
104	प्ले/प्री–प्राइमरी स्कूल की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति	
105	सीबीएसई/आईसीएसई/बीएसबी स्कूल की स्थापना के लिए एनओसी	
106	आरटीई के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन का नवीनीकरण	
107	इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के लिए अंक पत्र सह प्रमाणपत्र में सुधार के लिए आवेदन	
108	हाई स्कूल (कक्षा 10वीं) के लिए अंक पत्र सह प्रमाणपत्र में सुधार के लिए आवेदन	
109	इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के लिए डुप्लीकेट अंक पत्र सह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन	
110	हाई स्कूल (कक्षा 10वीं) के लिए डुप्लीकेट अंक पत्र सह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन	विद्यालयी शिक्षा
111	माइग्रेशन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन (कक्षा 10वीं)	
112	प्रति सेकंड ड्राइंग, मानचित्र, योजना और अनुभागों का अनुमोदन। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 (एफ)।	
113	650ट से अधिक वोल्टेज के लिए विद्युत स्थापना के ऊर्जाकरण से पहले CEI के अनुमोदन के लिए आवेदन (विनियम 43)	
114	विनियम 32 के अंतर्गत जनरेटिंग सेटों की विद्युत स्थापनाओं की स्वीकृति	
115	प्रति सेकंड ड्राइंग, मानचित्र, योजना और अनुभागों का अनुमोदन। विद्युत अधिनियम, 2003 के 53 (एफ) विनियम 32 (जनरेटर सेट) के तहत	विधुत्त निरीक्षक
116	धारा 54 के अंतर्गत अस्थायी विद्युत स्थापनाओं की स्वीकृति	
117	धारा 54 के तहत अस्थायी विद्युत प्रतिष्ठानों का पुनः परीक्षण	
118	विनियम 32 के तहत जनरेटिंग सेटों के विद्युत प्रतिष्ठानों का नवीनीकरण	
119	कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 27 के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन	
120	बाट माप और तौल यंत्रो के निर्माता के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन; कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उपाय	
121	बाट माप और तौल यंत्रो के डीलरों के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन; कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उपाय	
122	बाट माप और तौल यंत्रो का मरम्मत करने वालों के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन; कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उपाय	
123	बाट माप और तौल यंत्रो के सत्यापन/पुनरू सत्यापन के लिए आवेदन	
124	कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 27 के तहत पंजीकरण के लिए संशोधन	विधिक माप विज्ञान विभाग
125	कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 27 के तहत पंजीकरण के लिए समर्पण	
126	बाट माप और तौल यंत्रो के निर्माता के रूप में लाइसेंस में संशोधन; कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उपाय	
127	बाट माप और तौल यंत्रो के निर्माता के रूप में समर्पण लाइसेंस; कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उपाय	
128	बाट माप और तौल यंत्रो के निर्माता के रूप में लाइसेंस का नवीनीकरण कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उपाय	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
129	बाट माप और तौल यंत्रो के डीलर के रूप में लाइसेंस में संशोधन – कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उपाय	
130	बाट माप और तौल यंत्रो के डीलर के रूप में समर्पण लाइसेंस; कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उपाय	
131	बाट माप और तौल यंत्रो के डीलर के रूप में लाइसेंस का नवीनीकरण कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उपाय	
132	बाट माप और तौल यंत्रो का मरम्मत करने वालों के रूप में लाइसेंस में संशोधन कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उपाय	
133	बाट माप और तौल यंत्रो का मरम्मतकर्ता के रूप में समर्पण लाइसेंस कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उपाय	
134	बाट माप और तौल यंत्रो का मरम्मतकर्ता के रूप में लाइसेंस का नवीकरण कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उपाय	
135	सेवानिवृत्ति होने वाले पदधारी को पेंशन प्रपत्र अग्रसारित किया जाना	वित्त विभाग
136	मृत्यु के मामलों में पेंशन प्रपत्र का भरा जाना	
137	पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण	
138	अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री/विकलांग/मानसिक रूप से विक्षिप्त संतान को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता	
139	राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना तथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बन्धित ''बीमा योजना'' के अन्तर्गत भुगतान	
140	सेवानिवृत्त/मृतक सरकारी सेवकों को अवकाश नकदीकरण का भुगतान/अन्तर की धनराशि का भुगतान	
141	सेवानिवृत्त/दिवगंत सरकारी सेवकों को सामन्य भविय निर्वाह निधि खाते में जमा धनराशि का अविलम्ब अंतिम भुगतान/ निर्धारित प्रकिया का त्वरित अनुपालन (क) जमा धनराशि का 90 प्रतिशत का भुगतान (ख) शेष 10 प्रतिशत का भुगतान	
142	राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत भुगतान का सत्यापन।	
143	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना/ अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए आवेदन	चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
144	विभागीय सिविल कार्यों हेतु ठेकेदारों का पंजीयन	
145	विभागीय विद्युतीय कार्यों हेतु ठेकेदारों का पंजीयन	
146	नया सबमिशन (हरिद्वार)	हरिद्वार विकास प्राधिकरण
147	कंपाउंडिंग (हरिद्वार)	
148	कंपाउंडिंग (अल्मोड़ा)	जिला विकास प्राधिकरण (अल्मोड़ा)
149	सेल्फ कंपाउंडिंग	
150	जोड़ परिवर्तन (अल्मोड़ा)	
151	संशोधन (अल्मोड़ा)	
152	विस्तार (अल्मोड़ा)	
153	लेआउट स्वीकृति (अल्मोड़ा)	
154	वन टाइम सेटलमेंट (अल्मोड़ा)	
155	प्लिंथ स्तर का निरीक्षण (अल्मोड़ा)	
156	इंटरमीडिएट निरीक्षण (अल्मोड़ा)	
157	समापन (अल्मोड़ा)	
158	अधिभोग (अल्मोड़ा)	
159	होम्योपैथिक दवाओं को बेचने, स्टॉक करने, प्रदर्शन करने, बिक्री के प्रस्ताव या वितरित करने हेतु फुटकर लाइसेंस के लिए आवेदन	होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें
160	होम्योपैथिक दवाओं को बेचने, स्टॉक करने, प्रदर्शन करने, बिक्री के प्रस्ताव या वितरित करने हेतु थोक लाइसेंस के लिए आवेदन	
161	होम्योपैथिक दवाओं को बेचने, स्टॉक करने, प्रदर्शन करने, बिक्री के प्रस्ताव या वितरित करने हेतु फुटकर लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
162	होम्योपैथिक दवाओं को बेचने, स्टॉक करने, प्रदर्शन करने, बिक्री के प्रस्ताव या वितरित करने हेतु थोक लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन	
163	एयरो स्पोर्ट (गैर–वाणिज्यिक) के लिए आवेदन	पर्यटन विभाग
164	चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण	
165	होमस्टे के लिए पंजीकरण	
166	यात्रा व्यापार के लिए पंजीकरण	
167	नया परिवार जोड़ने	पंचायती राज विभाग
168	परिवार रजिस्टर प्रतिलिपि	
169	परिवार पृथक्करण	
170	परिवार संशोधन	
171	निजी भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र	
172	शौचालय प्रमाण–पत्र	
173	लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें	परिवहन विभाग
174	ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें	
175	डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन करें	
176	डुप्लीकेट डीएल के लिए आवेदन करें	
177	पता बदलने के लिए आवेदन करें	
178	अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन करें	
179	डीएल निकालें	
180	शुल्क भुगतान	
181	आवेदन पत्र प्रिंट करें	
182	सेवा वापस लेना	
183	डीएल सेवाएं (डीएल/अन्य बदलने के लिए)	
184	एप्लिकेशन में वाहनों की श्रेणी जोड़ें	
185	नियुक्ति	
186	एलएल टेस्ट के लिए ट्यूटोरियल	
187	अपना लंबित आवेदन पूरा करें	
188	भुगतान की स्थिति जांचें	
189	दस्तावेज़ अपलोड करें	
190	ऑनलाइन एलएल टेस्ट (स्टॉल)	
191	डॉक्टर खोजें	
192	टैक्स का भुगतान करें	
193	स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करें	
194	फिटनेस नवीनीकरण के लिए आवेदन करें/फिटनेस विफल होने के बाद फिर से आवेदन करें	
195	भुगतान शेष शुल्क जुर्माना	
196	अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन	
197	डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट	
198	पंजीकरण का नवीनीकरण	
199	वाहन का संशोधन	
200	आरसी विवरण	
201	आरसी समर्पण	
202	मोबाइल नंबर अपडेट	
203	आवेदन वापस लेना	
204	नया पंजीकरण	पासपोर्ट सेवा
205	उपयोगकर्ता लॉगिन	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
206	आवेदन की स्थिति जांचें	
207	सामान्य प्रश्न	
208	सूचना का अधिकार	
209	नागरिक चार्टर	
210	वीजा सेवाएं	
211	कार्यालय का पता लगाएँ	
212	15mm व्यास जल कनेक्शन	पेयजल विभाग
213	20mm व्यास जल कनेक्शन	
214	25mm व्यास जल कनेक्शन	
215	32mm व्यास जल कनेक्शन	
216	40mm व्यास जल कनेक्शन	
217	50mm व्यास जल कनेक्शन	
218	50mm व्यास से अधिक जल कनेक्शन	
219	जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ मकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में एक सीवर संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना	
220	जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ किसी कालोनी अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठानों के समूह के लिये सीवर संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना	
221	जल संयोजन विच्छेदन	
222	सीवर संयोजन विच्छेदन एवं पुर्नसंयोजन	
223	जहाँ साध्य हो वहाँ पूर्व से स्थापित जल संयोजन/सीवर संयोजन का स्वामित्व या किरायेदारी का अन्तरण स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों मे अस्वीकृत करना	
224	जहाँ, तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ 15 एम0एम0 से 40 एम0एम0 व्यास के जल संयोजन का आकार बदलना	
225	जहाँ, तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ 50 एम0एम0 व्यास के जल संयोजन का आकार बदलना	
226	जहाँ, तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ 50 एम0एम0 व्यास से अधिक के जल संयोजन का आकार बदलना	
227	जहाँ साध्य हो वहाँ जल संयोजन /सीवर संयोजन में उपयोग में परिवर्तन	
228	जहाँ साध्य हो वहाँ अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करना	
229	जीवन प्रमाण / जीवित प्रमाण पत्र	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
230	पंजीकरण	
231	डाउनलोड	
232	भारतीय नागरिक/एनआरआई के लिए पैन कार्ड	पैन सेवायें आयकर
233	विदेशी नागरिक के रूप में पैन कार्ड के लिए आवेदन करें	
234	पैन कार्ड में बदलाव/सुधार	
235	ई–पैन डाउनलोड करें	
236	पुनर्मुद्रण पैन कार्ड	
237	ईकेवाईसी मोड के माध्यम से पैन डेटाबेस में पता अद्यतन करने की सुविधा	
238	पैन कार्ड ट्रैक करें	
239	पैन विस्तृत सत्यापन	
240	पैन और आधार लिंक स्थिति	
241	इंडेन	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
242	भारत गैस	
243	एचपी गैस	
244	कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत साइट योजना अनुमोदन	श्रम विभाग

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
245	बॉयलर निर्माता प्रमाणपत्र के लिए स्वीकृति	
246	ठेका श्रम अधिनियम, (विनियमन और उन्मूलन), 1970 के तहत लाइसेंस	
247	अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1979 के तहत ठेकेदार का लाइसेंस	
248	दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण और/या व्यापार लाइसेंस जारी करना	
249	पंजीकरण और कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत लाइसेंस प्रदान करना	
250	संविदा श्रम अधिनियम, 1970 के तहत प्रमुख नियोक्ता का पंजीकरण	
251	मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकरण	
252	अंतर–राज्य प्रवासी कामगार (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1979 के तहत प्रमुख नियोक्ता का पंजीकरण	
253	दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत दुकान तथा वाणिज्यिक अधिष्ठान का नवीनीकरण	
254	संविदा श्रम अधिनियम 1970 के अंतर्गत ठेकेदार एवं मुख्य नियोक्ता का नवीनीकरण	
255	औद्योगिक अधिष्ठान (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 के अंतर्गत स्थायी आदेश के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवादों का प्रमाणीकरण	
256	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्मकार अधिनियम (नियोजन तथा सेवा की शर्तें अधिनियम 1996 के अंतर्गत अधिष्ठान तथा श्रमिकों का पंजीकरण	
257	बॉयलर अधिनियम 1923 के अंतर्गत अधिष्ठानों का नवीनीकरण	
258	महिला प्रधान बचत क्षेत्रीय योजना	राष्ट्रीय बचत विभाग
259	स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी सिस्टम	
260	नियुक्ति के लिए पंजीकरण करें	एन.एच.एम.
261	अधिभोग	राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
262	लेआउट स्वीकृति	
263	प्लिंथ स्तर का निरीक्षण	
264	इंटरमीडिएट निरीक्षण	
265	समापन	
266	बिल्डिंग प्लान अप्रूवल (CTE)	
267	नया सबमिशन	
268	संशोधन	
269	वन टाइम सेटलमेंट	
270	अतिरिक्त परिवर्तन	
271	विस्तार	
272	कंपाउंडिंग	
273	स्व प्रमाणन	
274	स्थाई निवास प्रमाण पत्र	राजस्व विभाग
275	चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी)	
276	चरित्र प्रमाण पत्र (सामान्य)	
277	हैसियत प्रमाण पत्र	
278	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र	
279	पर्वतीय प्रमाण पत्र	
280	उत्तरजीवी प्रमाण पत्र	
281	जाति प्रमाण पत्र	
282	आय प्रमाण पत्र	
283	स्टाम्प विक्रेता लाइसेन्स	
284	साहूकारी व्यवसाय लाइसेन्स	
285	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
286	अरायज नवीश लाइसेन्स	
287	चरित्र सत्यापन (राजस्व पुलिस क्षेत्रांतर्गत)	
288	दैवीय आपदा आर्थिक सहायता (रु 10,000 तक)	
289	दैवीय आपदा आर्थिक सहायता (रु 50,000 तक)	
290	दैवीय आपदा आर्थिक सहायता (रु 50,000 से अधिक)	
291	मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि का वितरण	
292	सार्वजनिक आरओआर	
293	किसान का पंजीकरण	रेशम निदेशालय
294	रेशम उत्पादन के लिए खाद्य पोधों की मांग के लिए आवेदन	
295	नर्सरी स्थापना एवं रख–रखाव हेतु तकनीकी जानकारी एवं सुझाव हेतु आवेदन	
296	रेशमकीट पालन इकाई उपकरणों की मांग के लिए आवेदन	
297	रेशमकीट पालन गृह के स्वच्छताकरण हेतु आवेदन	
298	टिकट आरक्षण	रेलवे
299	पीएनआर स्थिति प्राप्त करें	
300	ट्रेन शेड्यूल चेक करने के लिए	
301	भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र	शहरी विकास निदेशालय
302	सड़कों की सफाई	
303	स्ट्रीट लाईट्स का रख–रखाव	
304	पालतू जानवरों को रखने का रजिस्ट्रेशन	
305	मोबाईल टावर हेतु अनापत्ति प्रदान करना	
306	सी0 एंड डी वेस्ट उठाना	
307	नाली / नालों की सफाई	
308	मृत पशुओं का निस्तारण।	
309	आवारा पशुओं को पकड़ना	
310	मूल अंक पत्र जारी करने हेतु आवेदन (केवल यू.जी. / पी.जी. / डिप्लोमा छात्रों के लिए)	संस्कृत शिक्षा विभाग
311	अस्थायी उपाधि प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन (केवल यू.जी. / पी.जी. / डिप्लोमा छात्रों के लिए)	
312	उपाधि प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन (केवल यू.जी. / पी.जी. / डिप्लोमा छात्रों के लिए)	
313	प्रवजन प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन	
314	डुप्लीकेट उपाधि प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन (केवल यू.जी. / पी.जी. / डिप्लोमा छात्रों के लिए)	
315	डुप्लीकेट अंक–पत्र जारी करने हेतु आवेदन (केवल यू.जी. / पी.जी. / डिप्लोमा छात्रों के लिए)	
316	मूल अंक पत्र जारी करने हेतु आवेदन (केवल पीएच.डी छात्रों के लिए)	
317	अस्थायी उपाधि प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन (केवल पीएच.डी छात्रों के लिए)	
318	उपाधि प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन (केवल पीएच.डी छात्रों के लिए)	
319	डुप्लीकेट उपाधि प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन (केवल पीएच.डी छात्रों के लिए)	
320	डुप्लीकेट प्रवजन प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन	
321	डुप्लीकेट अंक–पत्र जारी करने हेतु आवेदन (केवल पीएच.डी छात्रों के लिए)	
322	सुधार कर सही प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन	
323	सुधार कर सही अंक पत्र जारी करने हेतु आवेदन	
324	स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन	
325	स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन (काउंटर हस्ताक्षर)	
326	डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन	
327	डुप्लीकेट अंक पत्र जारी करने हेतु आवेदन	
328	उत्तीर्ण छात्रों के लिए मूल प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
329	मूल अंक पत्र जारी करने हेतु आवेदन	
330	रद्द परीक्षा परिणाम पर निर्णय हेतु आवेदन	
331	अधूरा /गलत परिणाम के सुधार पर निर्णय हेतु आवेदन	
332	रोक परिणाम पर निर्णय हेतु आवेदन	
333	वृद्धावस्था पेंशन	समाज कल्याण विभाग
334	विकलांगता भत्ता	
335	विधवा पेंशन	
336	विकलांगता रखरखाव अनुदान	
337	किसान पेंशन	
338	तीलू रौतेली पेंशन	
339	परित्याग पेंशन	
340	बौना पेंशन	
341	शादी अनुदान फॉर्म	
342	पूर्व सैनिक रोजगार पंजीकरण	सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड
343	पूर्व सैनिक पंजीकरण योग्यता संसोधन	
344	पूर्व सैनिक नवीनीकरण रोजगार पंजीकरण	
345	पूर्व सैनिक आई कार्ड	
346	गृह कर में छूट हेतु चिन्हीकरण	
347	अशोक चक्र श्रृंखला (अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र) के पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त नकद / वार्षिकी के भुगतान हेतु	
348	विशेष सेवा के बदले एकमुश्त नकद अनुदान (परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल (उत्कृष्ट)	
349	राज्य सरकार द्वारा वीर चक श्रृंखला पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त नकद / वार्षिकी पुरस्कार (परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र)	
350	राज्य के सैनिकों को युद्ध सेवा / वीरता पदक के लिए एकमुश्त नकद अनुदान / वार्षिकी (सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल (गैलेन्ट्री), मेंशन–इन–डिस्पैच)	
351	रोजगार पंजीकरण	सेवायोजन विभाग
352	पंजीकरण योग्यता संसोधन	
353	रोजगार पंजीकरण नवीनीकरण	
354	विदेशों में रोजगार हेतु पंजीकरण	
355	प्रस्तुत विलेखों को निबंधन हेतु स्वीकार किये जाने पर पंजीकृत किया जाना।	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग
356	पंजीकृत विलेखों को पंजीकरण की कार्यवाही के पश्चात् वापस किया जाना।	
357	अनिवार्य विवाह संबंधी प्रार्थना–पत्रों को रजिस्ट्रीकरण हेतु स्वीकार किया जाना।	
358	भारमुक्त निर्माण पत्र	
359	अनिवार्य विवाह प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना।	
360	निरीक्षण से संबंधित आवेदनों का निस्तारण।	
361	साधारण नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।	
362	प्रतिलिपि सामान्य को लौटा दी जाएगी।	
363	प्रति के लिए आवेदन जमा करना आवश्यक है।	
364	प्रति लौटानी होगी।	
365	नकल के लिए आवेदन जमा करना बहुत महत्वपूर्ण है।	
366	प्रतिलिपि तत्काल वापस की जाए।	
367	भूमि/भूखंड आवंटन के लिए आवेदन	स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
368	आवंटित प्लॉट का समय विस्तार	
369	भूखंडों का समर्पण	
370	स्थानांतरण अनुमति के लिए आवेदन	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
371	पानी कनेक्शन के लिए आवेदन	कार्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड
372	बंधक अनुमति के लिए आवेदन	
373	आवंटी संगठन के पुनर्गठन के लिए आवेदन	
374	प्लाटों/इकाइयों के सबलेटिंग/सब–लीज के लिए आवेदन	
375	आवंटी संगठन के नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन	
376	उत्पाद परिवर्तन अनुमति के लिए आवेदन	
377	निरस्त भूखंडों के आवंटन की बहाली	
378	एमएसएमई नीति 2015 के तहत ब्याज सब्सिडी का दावा	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
379	एमएसएमई नीति 2015 के तहत बिजली बिलों की प्रतिपूर्ति	
380	एमएसएमई नीति 2015 के तहत राज्य परिवहन सब्सिडी का दावा	
381	एमएसएमई के तहत पूंजीगत सब्सिडी	
382	एमएसएमई के तहत स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए प्रोत्साहन का दावा करने के लिए आवेदन	
383	एमएसएमई के तहत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए प्रोत्साहन का दावा करने के लिए आवेदन	
384	एमएसएमई नीति के तहत इंटरनेट शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए प्रोत्साहन का दावा करने के लिए आवेदन	
385	एमएसएमई के तहत उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए प्रोत्साहन का दावा करने के लिए आवेदन	
386	एमएसएमई के तहत आईएसओ शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए प्रोत्साहन का दावा करने के लिए आवेदन	
387	अनुरोध प्रस्तुत करें	सूचना का अधिकार
388	प्रथम अपील सबमिट करें	
389	स्थिति देखें	
390	नवीन उद्यान कार्ड जारी करना	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
391	पुराने उद्यान कार्ड का नवीनीकरण	
392	कृषि भूमि में फलदार वृक्षों के पातन का अनापत्ति प्रमाण–पत्र	
393	वर्षाकालीन फल पौध उपलब्ध कराना	
394	शीतकालीन फल पौध उपलब्ध कराना	
395	सब्जी बीज उपलब्ध कराना	
396	सब्जी पौध उपलब्ध कराना	
397	पुष्प बीज/कन्द/पौध उपलब्ध कराना	
398	मसाला बीज/कन्द उपलब्ध कराना	
399	घेरबाड़ की योजना	
400	खाद्य प्रसंस्करण में एक वर्षीय डिप्लोमा	
401	मौनपालन प्रशिक्षण	
402	माली प्रशिक्षण	
403	मशरूम प्रशिक्षण	
404	मौनवंश/मौनबॉक्स उपलब्ध कराना	
405	पुराने उद्यानों का जीर्णोंद्वार	
406	तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन एवं विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन	
407	पॉलीहॉउस स्थापना के लिए आवेदन	
408	शैडनेट हाउस स्थापना के लिए आवेदन	
409	प्लास्टिक टनल की स्थापना के लिए आवेदन	
410	एंटी हैलनेट स्थापना के लिए आवेदन	
411	प्लास्टिक मल्चिंग स्थापना के लिए आवेदन	
412	वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना के लिए आवेदन	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
413	ट्यूब वैल / बोर वैल की स्थापना के लिए आवेदन	
414	पैकहाउस स्थापना के लिए आवेदन	
415	मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन के लिए आवेदन	
416	मशरूम उत्पादन के लिए आवेदन	
417	मशरूम स्पॉन उत्पादन के लिए आवेदन	
418	DIPR	डीआईपीआर
419	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन	उच्च शिक्षा विभाग
420	स्थानांतरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन	
421	विश्वविद्यालयों की सूची	
422	कॉलेजों की सूची	
423	कॉलेजों का प्रोफाइल	
424	स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्
425	चरित्र प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवेदन	
426	जमानत राशि की वापसी के लिए आवेदन	
427	अनंतिम अंकतालिका जारी करने के लिए आवेदन	
428	डिप्लोमा प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवेदन	
429	माइग्रेशन प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवेदन	
430	अंकपत्र त्रुटि सुधार करने के लिए आवेदन	
431	डिप्लोमा प्रमाण–पत्र में त्रुटि सुधार करने के लिए आवेदन	
432	डुप्लिकेट अंकपत्र जारी करने के लिए आवेदन	
433	डुप्लिकेट डिप्लोमा प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवेदन	
434	अनंतिम अंकतालिका में त्रुटि सुधार करने के लिए आवेदन	
435	उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिये आवेदन	
436	प्रतिलेख प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवेदन	
437	अनंतिम डिप्लोमा प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवेदन	
438	वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत स्थापना के लिए सहमति – ताज़ा	उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
439	जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम, 1981 के तहत समेकित सहमति और प्राधिकरण और खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आंदोलन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण – ताज़ा	
440	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण	
441	ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के तहत प्राधिकरण और पंजीकरण	
442	बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन	
443	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण	
444	जैव चिकित्सा अपशिष्ट	
445	वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत स्थापना के लिए सहमति – विस्तार	
446	जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम, 1981 के तहत समेकित सहमति और प्राधिकरण और खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आंदोलन) नियमों के तहत प्राधिकरण – विस्तार	
447	वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत स्थापना के लिए सहमति – विस्तार	
448	जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम, 1981 के तहत समेकित सहमति और प्राधिकरण और खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आंदोलन) नियमों के तहत प्राधिकरण – नवीनीकरण	
449	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण के लिए नवीनीकरण	
450	ई–अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 2016 के तहत नवीनीकरण	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
451	बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवीनीकरण	
452	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण के लिए नवीनीकरण	
453	जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु नवीनीकरण	
454	नया घरेलू कनेक्शन (LT)	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
455	नए कनेक्शन के लिए आवेदन एलटी लाइन – गैर घरेलू/औद्योगिक	
456	अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन – एलटी लाइन	
457	नए कनेक्शन एच टी लाइन के लिए आवेदन – गैर घरेलू/औद्योगिक	
458	लोड बढ़ाने के लिए आवेदन	
459	अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन – एचटी लाइन	
460	नए कनेक्शन के लिए आवेदन एलटी लाइन– गैर घरेलू/औद्योगिक (5 किलोवाट तक)	
461	नए कनेक्शन के लिए आवेदन एचटी लाइन– गैर घरेलू/औद्योगिक 200 किलोवाट तक	
462	जले मीटरों को बदलना	
463	वोल्टेज में उतार–चढ़ाव (स्थानीय समस्या)	
464	परिवर्तक की टेपिंग	
465	वितरण परिवर्तक/लाईन/कैपेसिटर की मरम्मत	
466	एच०टी०/एल०टी० प्रणाली की स्थापना एवं उच्चीकरण	
467	वोल्टेज के उतार–चढ़ाव के कारण उपभोक्ता उपकरणों की क्षति	
468	जहाँ नये एल0टी0 संयोजन को प्रदान करने हेतु मौजूदा नेटवर्क में कोई विस्तार कि आवश्यकता न हो	
469	जहाँ नये एल0टी0 संयोजन को प्रदान करने हेतु मेंस को विस्तार करने की आवश्यकता हो	
470	जहाँ नये एल0टी0 संयोजन को प्रदान करने हेतु नये 11/0.4 के0वी0 उपस्थान को स्थापित करने की आवश्यकताहै	
471	जहाँ नये एल०टी० संयोजन को प्रदान करने हेतु नये 33/11 के०वी० उपस्थान को स्थापित करने की आवश्यकता हो	
472	जहाँ संयोजन 11 के0वी0विभव पर गैर स्वतन्त्र पोषक से निर्गत किया जाना प्रस्तावित हो	
473	जहाँ संयोजन 11 के०वी० विभव पर स्वतन्त्र पोषक से निर्गत किया जाना प्रस्तावित हो	
474	जहाँ संयोजन 33 के0वी0विभव पर निर्गत किया जाना प्रस्तावित हो	
475	जहाँ संयोजन 132 के0वी0व उससे अधिक विभव पर निर्गत किया जाना प्रस्तावित हो	
476	जहाँ संयोजन हेतु नये 33/11 के०दी० उपस्थान के स्थापना की आवश्यकता हो	
477	जहाँ संयोजन हेतु 33/11 के०वी० उपस्थान की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता हो	
478	जहाँ संयोजन हेतु 33/11 के0वी0 उपस्थान पर ष्बेष के विस्तारीकरण की आवश्यकता हो	
479	जहाँ संयोजन हेतु नये 132 के०वी० व उससे अधिक विभव के उपस्थान के स्थापना की आवश्यकता हो	
480	जहाँ संयोजन हेतु 132 के०बी० व उससे अधिक विभव के उपस्थान पर ष्बे ९ के विस्तारीकरण की आवश्यकता हो	
481	एल.टी. संयोजन हेतु जहाँ लाईनों/उपस्थानों में परिवर्तन की आवश्यकता न हो	
482	एच०टी०/ ई०एच०टी० संयोजन हेतु जहाँ लाईनों / उपस्थानों में परिवर्तन की आवश्यकता न हो	
483	जहाँ लाईनों / उपस्थानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो ।	
484	फ्यूज का उड़ना या एम0सी0बी0/एम0सी0सी 0बी0 ट्रिप होने पर विद्युत आपूर्ति बहाली की निर्धारित समय सीमा (जहाँ फ्यूज या एम0सी0बी0/ एन0सी0बी0 विभाग की है)	
485	सर्विस लाईन का टूटना या सर्विस लाईन का खंभे से निकल / टूट जाना।	
486	एल0टी0 वितरण लाईन / प्रणाली में दोष	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
487	वितरण परिवर्तक का विफल होना/जलना	
488	एच0टी0 (11 के0वी0 व 33 के0वी0) मेन्स का विफल होना फ्यूज का उड़ना, सविर्तस लाईन का टूटना या अन्य कोई दोष।	
489	33/के0वी0 उपस्थान में समस्या	
490	पॉवर परिवर्तक की विफलता	
491	मीटर की परिशुद्धता परीक्षण के लिये की गयी शिकायत	
492	संपत्ति पर स्वामित्व / कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन	
493	उपभोक्ता के नाम का कानूनी वारिस को हस्तान्तरण	
494	श्रेणी में परिवर्तन	
495	बिलिंग से सम्बन्धित शिकायत	
496	परिसर खाली करने दखल के परिवर्तन पर अन्तिम बिल जारी करना ।	
497	उपभोक्ता के अनुरोध पर स्थाई विच्छेदन के उपरान्त बिलिंग	
498	पुनः संयोजन चाहने वाले उपभोक्ता	
499	विच्छेदन चाहने वाले उपभोक्ता	
500	नवीनतम बिल	
501	योजनाओं	उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
502	स्वयंसेवी पंजीकरण यूएसडीएमए	
503	एनजीओ पंजीकरण यूएसडीएमए	
504	Covid–19 मृत्यु मुआवजा	
505	मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना	उत्तराखंड स्वरोजगार योजनाएं
506	मुख्यमंत्री सौर स्व–रोजगार योजना	
507	मुख्यमंत्री स्वरोगजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो)	
508	वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना	
509	दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना	
510	जल कनेक्शन हेतु आवेदन	उत्तराखंड जल संस्थान
511	जहां भी तकनीकी रूप से संभव हो, भवन/वाणिज्यिक संस्थानों में नए सीवर कनेक्शन की मंजूरी अन्यथा विशेष परिस्थिति में अस्वीकृति	
512	जहां भी तकनीकी रूप से संभव हो, किसी कॉलोनी या संस्थान/संस्थानों के समूह में नए सीवर कनेक्शन की मंजूरी देना, अन्यथा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृति	
513	यूजेएस द्वारा जल कनेक्शन की उपलब्धता के लिए एनओसी	
514	उपभोक्ता सूचना	
515	उपभोक्ता बिल की जानकारी	
516	ऑनलाइन भुगतान	
517	नए कनेक्शन की स्थिति	
518	नया कनेक्शन भुगतान (उपयोगकर्ता)	
519	स्थापना पूर्व फायर एनओसी के लिए आवेदन	अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग
520	प्री–ऑपरेशनल फायर एनओसी के लिए आवेदन	
521	वार्षिक क्लीयरेंस प्रमाणपत्र	
522	नया सबमिशन	उत्तराखंड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण
523	सेल्फ कंपाउंडिंग	
524	ओटीएस–2021	
525	लेआउट अनुमोदन	
526	कंपाउंडिंग	
527	परिवर्धन एवं परिवर्तन/संशोधन	
528	समय विस्तार	
529	निरीक्षण	
530	अधिभोग	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
531	स्थापना के लिए सहमति (सीटीई)	
532	लेआउट का पुनरावलोकन	
533	संशोधित मानचित्र	
534	संचालन की सहमति (सीटीओ)	
535	आंशिक अधिभोग	
536	विन्यास	
537	सीटीई स्व–प्रमाणन	
538	स्व–प्रमाणन UHUDA	
539	प्रत्यक्ष समापन	
540	वृक्ष पातन अनुज्ञा	
541	वृक्ष अभिवहन पास	
542	पेड़ काटने के लिए एनओसी	वन विभाग
543	वृक्ष पारगमन परमिट (ईओडीबी)	
544	जंगल से दूरी का पत्र	
545	वोट पंजीकरण	
546	अपने मतदाता पंजीकरण की स्थिति की पुष्टि करें	
547	मतदाता सूची में नाम खोजें	
548	एनआरआई मतदाता के रूप में नामांकन करें	चुनाव आयोग
549	अपने मतदान केंद्र को जानें	
550	शिकायतें दर्ज करें	
551	अपनी शिकायत को ट्रेक करें	
552	नया पंजीकरण	
553	ट्रेक एप्लिकेशन स्थिति	
554	स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए आवेदन	
555	चालान बनाएं	
556	ट्रेक भुगतान स्थिति	
557	भुगतान के खिलाफ शिकायत (जीएसटी पीएमटी–07)	
558	एचएसएन कोड खोजें	
559	कारण सूची	जीएसटी
560	जीएसटी प्रैक्टिशनर (जीएसटीपी) का पता लगाएँ	
561	अपंजीकृत आवेदक के लिए यूजर आईडी जेनरेट करें	
562	खोज अग्रिम निर्णय	
563	बीओई खोजें	
564	ई–वे बिल सिस्टम	
565	ई–वे बिल पंजीकरण	
566	ट्रांसपोर्टरों के लिए नामांकन	
567	नागरिकों के लिए ई–वे बिल	
568	प्रमाण पत्र प्राप्त करे	
569	केंद्र का पता लगाएं	जीवन प्रमाण
570	एप्लिकेशन डाउनलोड करे	
571	ई–कोर्ट सेवाएं	
572	मामले की स्थिति	
573	कोर्ट कॉम्प्लेक्स का चयन करें	
574	याचिकाकर्ता / प्रतिवादी	न्याय विभाग
575	न्यायालय के आदेश	
576	आभासी न्यायालय	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
577	ई–कोर्ट शुल्क भुगतान	
578	न्यायालय शुल्क	
579	न्यायिक जमा	
580	वायु सेवा	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
581	उड़ान बुक करें	
582	उड़ान की जानकारी	
583	उड़ान ट्रैकिंग	
584	उड़ान के शेड्यूल्स	
585	उड़ान की वर्तमान स्थिति	
586	शिकायत और रसीद का प्रसंस्करण	
587	नई शिकायत की रिपोर्ट करें	
588	हवाई अड्डे की जानकारी	
589	NFSA के राशन कार्ड का नवीनीकरण/संशोधन/निस्तारीकरण/स्थानान्तरण	नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
590	राज्य खाद्य योजना के राशन कार्ड का नवीनीकरण / संशोधन/ निस्तारीकरण /स्थानान्तरण करना	
591	कुत्ते के लाइसेंस के लिए आवेदन करें	नगर निगम देहरादून
592	संपत्ति कर	नगर सेवा
593	व्यापार लाइसेंस	
594	लाइसेंस का नवीनीकरण	
595	सड़क काटना	
596	नियुक्ति के लिए पंजीकरण करें	स्वास्थ्य–ORS
597	तत्काल ई–पैन कार्ड के लिए आवेदन करें	आयकर
598	ई–सत्यापन रिटर्न	
599	कर का ई–भुगतान	
600	आधार को पैन कार्ड से लिंक करें	
601	आईटीआर स्टेटस चेक करें	
602	भुगतान की स्थिति जानें	
603	आयकर की ई–फाइलिंग	
604	आधार–पैन लिंक की स्थिति की जांच करने के लिए	
605	आईटीडी द्वारा जारी नोटिस/आदेश प्रमाणित करें	
606	कर चोरी याचिका या बेनामी संपत्ति होल्डिंग जमा करें	
607	दोष सिद्ध न होने का प्रमाण–पत्र	आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं
608	निरूशुल्क बिक्री प्रमाण–पत्र	
609	वैधता प्रमाण–पत्र	
610	निष्पादन प्रमाण–पत्र	
611	विनिर्माण अनुभव प्रमाण–पत्र	
612	नया जीएमपी प्रमाण पत्र	
613	आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन	
614	आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी दवाओं के विनिर्माण लोन लाइसेंस आवेदन	
615	आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन	
616	आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी दवाओं के विनिर्माण लोन लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन	
617	अतिरिक्त शास्त्रीय दवाओं के निर्माण के लिए आवेदन	
618	अतिरिक्त पेटेंट दवाओं के निर्माण के लिए आवेदन	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
619	अतिरिक्त शास्त्रीय एवं पेटेंट दवाओं के निर्माण के लिए आवेदन	
620	क्लबों को बार लाइसेंस के लिए आवेदन	आबकारी विभाग
621	रेस्तरां को बार लाइसेंस के लिए आवेदन	
622	बीयर बार को बार लाइसेंस के लिए आवेदन	
623	ब्रूवरी लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन	
624	ब्रूवरी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन	
625	डिस्टिलरी लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन	
626	डिस्टिलरी लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए आवेदन	
627	बंधित गोदाम लाइसेंस के लिए आवेदन	
628	बंधित गोदाम लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन	
629	शराब परोसने के लिए मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल/सामुदायिक हॉल/होटल आदि को दैनिक आधार पर बार लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन	
630	शराब परोसने के लिए मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल/सामुदायिक हॉल/होटल आदि को लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनिवार्य वार्षिक पंजीकरण	
631	नए थोक लाइसेंस के लिए आवेदन (CL–2)	
632	नवीकरण थोक लाइसेंस के लिए आवेदन (CL–2)	
633	नए थोक लाइसेंस के लिए आवेदन (FL–2)	
634	नवीकरण थोक लाइसेंस के लिए आवेदन (FL–2)	
635	नए थोक लाइसेंस के लिए आवेदन (FL&2B)	
636	नवीकरण थोक लाइसेंस के लिए आवेदन (FL&2B)	
637	बार लाइसेंस का नवीनीकरण	
638	नारकोटिक ड्रग्स लाइसेंस (NDLS) के लिए आवेदन	
639	शुद्ध अल्कोहल लाइसेंस के लिए आवेदन (FL–43)	
640	FL–5 (मॉल/डिपार्टमेंटल स्टोर)	
641	FLM–3 (बॉटलिंग प्लांट)	
642	FL–99A (फुटकर बिक्री के लिए कैंटीन स्टोर विभाग)	
643	वाइनरी के लिए लाइसेंस	
644	FL2A– कैंटीन स्टोर्स विभाग के लिए थोक लाइसेंस	
645	ब्रांड पंजीकरण और लेबल	
646	अस्थायी बार लाइसेंस प्रदान करने	
647	प्राथमिक/माध्यमिक संस्थानों को मदरसा की मान्यता के लिए पंजीकरण	अल्पसंख्यक कल्याणकारी निदेशालय
648	उच्च माध्यमिक संस्थानों को मदरसा की मान्यता के लिए पंजीकरण	
649	स्नातक/स्नातकोत्तर संस्थानों को मदरसा की मान्यता के लिए पंजीकरण	
650	प्राथमिक/माध्यमिक संस्थानों के लिए मदरसा की मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन	
651	उच्च माध्यमिक संस्थानों के लिए मदरसा की मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन	
652	स्नातक/स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए मदरसा की मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन	
653	एफ0आई0आर0 की प्रति वादी को उपलब्ध कराना	गृह विभाग
654	सामान्य प्रार्थना पत्रों/शिकायतों का निस्तारण	
655	पुलिस के विरूद्ध शिकायत	
656	चरित्र सत्यापन (पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, सेना सत्यापन रिपोर्ट, निजी सत्यापन रिपोर्ट) किया जाना	
657	गुमशुदगी की रिपोर्ट का पंजीकरण	
658	ऑनलाईन शिकायत पर कार्यवाही	
659	किरायेदार का सत्यापन 1–प्रदेश के अन्दर 2–प्रदेश के बाहर	
660	नौकर सत्यापन 1–प्रदेश के अन्दर 2–प्रदेश के बाहर	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
661	दस्तावेजों / मोबाईल आदि के खो जाने की रिपोर्ट करना	
662	अर्द्ध सरकारी नौकरियो के लिये चरित्र सत्यापन (प्रमाण–पत्र (चरित्र एटिसडेंट)	
663	भारतीय नागरिकों के लिये विदेश जाने हेतु पुलिस मंजूरी प्रमाण–पत्र (प्रमाण–पत्र (चरित्र एटिसडेंट)	
664	भारतीय नागरिकों के लिये विदेश जाने हेतु पुलिस क्लीरियेन्स सार्टिफिकेट (अध्ययन/नौकरी के लिये वीजा)	
665	संस्थाओं /कम्पनियों के लिये पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र	
666	किरायेदार/ नौकर सत्यापन (यदि स्थानीय क्षेत्रों के निवासी हैं)	
667	चरित्र–सत्यापन (यदि व्यक्ति विगत 3 वर्ष में आवेदन देने वाले ज़िले में एक ही स्थान में निवासरत रहा हो)	
668	संविदा के लिये चरित्र सत्यापन पर निर्णय	
669	शिकायत पर की गयी कार्यवाही की सूचना (FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट) /DDR (दैनिक डायरी रजिस्टर)/ मामला निक्षेपित	
670	बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन (अन्य जनपदों से प्राप्त सत्यापन पत्र जहाँका वह रहने वाला है)	
671	सेवायोजन सम्बन्धी सत्यापन	
672	चोरी के मामलों में अनावरित रिपोर्ट की प्रति	
673	सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स के लिए एनओसी	
674	भवन की अग्नि सुरक्षा के लिए एनओसी	
675	गैस/तेल डिपो के लिए एनओसी	
676	गैस गोदाम एवं एजेंसी हेतु एनओसी	
677	पेट्रोल पंप/सीएनजी स्टेशन के लिए एनओसी	
678	हथियार बेचने के लाइसेंस के लिए एनओसी	
679	हथियार रखने के लाइसेंस के लिए एनओसी	
680	हथियारों की मरम्मत के लाइसेंस के लिए एनओसी	
681	हथियार बेचने के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एनओसी	
682	हथियार रखने के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एनओसी	
683	हथियारों की मरम्मत के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एनओसी	गृह विभाग
684	आतिशबाजी बेचने के लाइसेंस के लिए एनओसी	
685	आतिशबाजी भंडारण के लाइसेंस के लिए एनओसी	
686	आतिशबाजी निर्माण के लाइसेंस के लिए एनओसी	
687	सल्फर की बिक्री के लिए एनओसी	
688	अग्नि रिपोर्ट	
689	राहत कार्य रिपोर्ट	
690	बचाव रिपोर्ट	
691	विस्फोटक के भंडारण/पत्रिका के लिए एनओसी	
692	खेलों के आयोजन के लिए एनओसी	
693	सार्वजनिक समारोह के आयोजन के लिए एनओसी	
694	हानिकारक और खतरनाक सामग्रियों के परिवहन की अनुमति के लिए अस्थायी अनुमति के लिए एनओसी	
695	मनोरंजन गतिविधियों की अस्थायी अनुमति के लिए एनओसी	
696	पटाखों की अस्थायी बिक्री के लिए एनओसी	
697	अन्य गतिविधियों की अस्थायी अनुमति के लिए एनओसी	
698	अस्थायी संरचना/पंडाल/मेला के लिए एनओसी	
699	फिल्म शूटिंग के लिए एनओसी	
700	हेलीपैड के लिए एनओसी	
701	लघु स्तर के केरोसीन/डीजल स्टेशन के लिए एनओसी	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
702	विदेशियों की भारत में रहने की अवधि बढ़ाया जाना	
703	विदेशियों का पंजीकरण	
704	विदेशी नागरिकों को पुलिस क्लेयरेंस प्रमाण–पत्र	
705	सड़क निर्माण हेतु ए श्रेणी में पंजीकरण	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग
706	भवन निर्माण हेतु ए श्रेणी में पंजीकरण	
707	विधुत कार्य हेतु ए श्रेणी में पंजीकरण	
708	सड़क निर्माण हेतु बी श्रेणी में पंजीकरण	
709	भवन निर्माण हेतु बी श्रेणी में पंजीकरण	
710	विधुत कार्य हेतु बी श्रेणी में पंजीकरण	
711	सड़क निर्माण हेतु सी श्रेणी में पंजीकरण	
712	भवन निर्माण हेतु सी श्रेणी में पंजीकरण	
713	विधुत कार्य हेतु सी श्रेणी में पंजीकरण	
714	सड़क निर्माण हेतु डी श्रेणी में पंजीकरण	
715	भवन निर्माण हेतु डी श्रेणी में पंजीकरण	
716	सड़क निर्माण हेतु ए श्रेणी में नवीनीकरण	
717	भवन निर्माण हेतु ए श्रेणी में नवीनीकरण	
718	विधुत कार्य हेतु ए श्रेणी में नवीनीकरण	
719	सड़क निर्माण हेतु बी श्रेणी में नवीनीकरण	
720	भवन निर्माण हेतु बी श्रेणी में नवीनीकरण	
721	विधुत कार्य हेतु बी श्रेणी में नवीनीकरण	
722	सड़क निर्माण हेतु सी श्रेणी में नवीनीकरण	
723	भवन निर्माण हेतु सी श्रेणी में नवीनीकरण	
724	विधुत कार्य हेतु सी श्रेणी में नवीनीकरण	
725	सड़क निर्माण हेतु डी श्रेणी में नवीनीकरण	
726	भवन निर्माण हेतु डी श्रेणी में नवीनीकरण	
727	ओपन पैन या भाप उबलने की प्रक्रिया के माध्यम से रब, खांडसारी चीनी बनाने के लिए पावर क्रशर के लिए आवेदन	
728	ओपन पैन या भाप उबलने की प्रक्रिया के माध्यम से गुड़ (गुड़) बनाने के लिए पावर क्रशर के लिए आवेदन	
729	ओपन पैन या भाप उबलने की प्रक्रिया के माध्यम से गुड़ (गुड़) के निर्माण के लिए पावर क्रशर के नवीनीकरण के लिए आवेदन	
730	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जॉब कार्ड	ग्रामीण विकास विभाग
731	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जॉब कार्ड धारक को श्रम रोजगार उपलब्ध कराना	
732	सड़क निर्माण हेतु ए श्रेणी में पंजीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
733	भवन निर्माण हेतु ए श्रेणी में पंजीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
734	सड़क निर्माण हेतु बी श्रेणी में पंजीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
735	भवन निर्माण हेतु बी श्रेणी में पंजीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
736	सड़क निर्माण हेतु सी श्रेणी में पंजीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
737	भवन निर्माण हेतु सी श्रेणी में पंजीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
738	भवन निर्माण हेतु डी श्रेणी में पंजीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
739	सड़क निर्माण हेतु डी श्रेणी में पंजीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
740	सड़क निर्माण के लिए ए श्रेणी में नवीनीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
741	भवन निर्माण के लिए ए श्रेणी में नवीनीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
742	सड़क निर्माण हेतु बी श्रेणी में नवीनीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
743	भवन निर्माण हेतु बी श्रेणी में नवीनीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
744	सड़क निर्माण हेतु सी श्रेणी में नवीनीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	

क्रमांक	सेवा का नाम	विभाग का नाम
745	भवन निर्माण हेतु सी श्रेणी में नवीनीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
746	सड़क निर्माण हेतु डी श्रेणी में नवीनीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
747	भवन निर्माण हेतु डी श्रेणी में नवीनीकरण (ग्रामीण निर्माण विभाग)	
748	A श्रेणी में पंजीकरण	लघु सिंचाई विभाग
749	B श्रेणी में पंजीकरण	
750	C श्रेणी में पंजीकरण	
751	D श्रेणी में पंजीकरण	
752	E श्रेणी में पंजीकरण	
753	A श्रेणी का नवीनीकरण (मौजूदा)	
754	B श्रेणी का नवीनीकरण (मौजूदा)	
755	C श्रेणी का नवीनीकरण (मौजूदा)	
756	D श्रेणी का नवीनीकरण (मौजूदा)	
757	E श्रेणी का नवीनीकरण (मौजूदा)	
758	A श्रेणी का नवीनीकरण (गैर–मौजूदा)	
759	B श्रेणी का नवीनीकरण (गैर–मौजूदा)	
760	C श्रेणी का नवीनीकरण (गैर–मौजूदा)	
761	D श्रेणी का नवीनीकरण (गैर–मौजूदा)	
762	E श्रेणी का नवीनीकरण (गैर–मौजूदा)	
763	मार्ग – अधिकार	
764	ठेकेदारों के पजींकरण– श्रेणी 'A'	
765	ठेकेदारों के पजींकरण– श्रेणी 'B'	
766	ठेकेदारों के पजींकरण– श्रेणी 'C'	
767	ठेकेदारों के पजींकरण – श्रेणी 'D'	

डी0बी0टी0 स्कीम के तहत निम्नलिखित 49 योजनाएं ''अपणि सरकार'' पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं तथा 23 योजनाएं आनलाईन किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

क्रमांक	योजना के नाम	विभाग का नाम
1	विकलांगता पेंशन योजना (0–18 वर्ष)	समाज कल्याण
2	विकलांगता पेंशन योजना (18 वर्ष+)	
3	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विवाह अनुदान	
4	किसान पेंशन योजना (एससी)	
5	किसान पेंशन योजना (एसटी)	
6	वृद्धावस्था पेंशन योजना (एससी)	
7	वृद्धावस्था पेंशन योजना (एसटी)	
8	वृद्धावस्था पेंशन योजना (सामान्य)	
9	विधवा पेंशन योजना (एसटी)	
10	विधवा पेंशन योजना (एससी)	
11	विधवा पेंशन योजना (सामान्य)	
12	कक्षा 1 से 8 तक के एससी छात्रों और आईटीआई छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	
13	विकलांगता पेंशन योजना(18+)	
14	परित्यक्त निराश्रित अविवाहित महिलाओं और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की	

क्रमांक	योजना के नाम	विभाग का नाम
	पत्नी के लिए पेंशन	
15	आश्रित विधवाओं की पुत्रियों के लिए विवाह अनुदान	
16	पहाड़ी क्षेत्रों में आदर्श मछली तालाब का निर्माण	अंतर्देशीय मत्स्य पालन
17	विशेष घटक उपयोजना	
18	जनजातीय उपयोजना	
19	मत्स्य पालन विविधीकरण योजना (एससीएसपी)	
20	मत्स्य पालन विविधीकरण योजना (टीएसपी)	
21	राज्य मत्स्य इनपुट योजना	
22	संस्कृत पथ्य पुस्तको का मुद्रां एवं निसुलक वितरण।	संस्कृत शिक्षा
23	संस्कृत विद्यालययो मे मेधावी छत्रो को चत्रवृति।	
24	अनुसूचित जनसंख्या के ब्यक्तियाओ की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना	जनजातीय मामले
25	अल्पसंख्याक समुदाय के मेधावी छात्र की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान	अल्पसंख्यक मामले
26	मुख्यमंत्री अल्पसंख्या प्रोत्साहन योजना	
27	भेड़ पालन योजना (एससी)	पशुपालन
28	महिला बकरी पालन योजना (सभी)	
29	गौ पालन योजना (एसटी)	
30	(एससी) के लिए बकरी पालन योजना	
31	गौ पालन योजना (एससी)	
32	(ST) के लिए बकरी पालन योजना	
33	भेड़ पालन योजना (एसटी)	
34	बकरी पालन योजना (सभी)	
35	दुग्ध उत्पदाको को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन (अनु0 28)।	डेयरी विकास
36	डेयरी विकास योजना (अनुदान 31)	
37	महिला डेयरी विकास योजना (अनुदान 30)	
38	दुग्ध उत्पादको को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन (अनुदान 30)।	
39	डेयरी विकास योजना (अनुदान 28)	
40	महिला डेयरी विकास योजना (अनुदान 28)।	
41	डेयरी विकास योजना (अनुदान 30)।	
42	महिला डेयरी विकास योजना (अनुदान 31)।	
43	अशोक चक्र श्रृंखला (अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कृतिचक्र) के विजेताओं के लिए राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार।	सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड
44	पेंशन के लिए अनुदान और विशेष सेवा के बदले पुरस्कार।	
45	राज्य सरकार द्वारा वीर चक्र विजेताओं को पूर्ण नकद पुरस्कार।	
46	राज्य के सैनिकों को युद्ध से लेकर सेना पदक तक एकमुश्त राज्य/वार्षिक अनुदान।	
47	राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार।	खेल विभाग
48	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता.	
49	विशिष्ट खिलाड़ियों को परदेसिया पुरस्कार।	

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा अपणि सरकार पोर्टल को प्रतिष्ठित **26वें राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है तथा देशभर में इस कार्यक्रम को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पहचान मिली है।

उत्तराखण्ड पी.एम. गतिशक्ति पोर्टल 'उन्नति' पोर्टल

'उन्नति' कार्यक्रम उत्तराखण्ड सरकार के विभागों के ऐसे प्रस्तावों और परियोजनाऐं, जो भारत सरकार में लंबित हैं तथा जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है, की वास्तविक स्थिति के अवलोकन एवं अनुश्रवण के लिए केंद्रीकृत प्रणाली है। 'उन्नति' कार्यक्रम के माध्यम से लंबित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करते हुए हितधारकों के बीच निर्बाध संचार प्रदान किया जा सकता है। उत्तराखण्ड पी.एम. गतिशक्ति पोर्टल विकसित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं–

(क) राज्य की पूँजीगत परियोजनाओं हेतु परियोजना प्रबन्धन मॉड्यूल।
(ख) मिसिंग लिंक, नाबार्ड, विशेष केन्द्रीय सहायता परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव मॉड्यूल।
(ग) विभागों के लिए वार्षिक वर्क–कैलेण्डर।
(घ) जनपदों के लिए 30 सूत्रीय समीक्षा फ्रेमवर्क।
(ङ.) बैठकों का कार्यवृत्त मॉड्यूल।
(च) अभिलेखों का भण्डारण व विभागों के मध्य अभिलेखों को साझा किये जाने की सुविधा।

मुख्यमंत्री हैल्प लाईन योजना "1905" (CM Help Line):–

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की सुविधा के साथ जन शिकायतों/समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रारम्भ की गयी सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 के अन्तर्गत कुल 67 विभागों, 215 उप विभागों के 4800 अधिकारी मैप्ड हैं। सी.एम. हैल्पलाईन '1905' को नये रूप में विकसित किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नई सुविधायें हैं–

(अ) माननीय मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के लिए एक विश्लेषक एवं समीक्षा डैशबोर्ड।
(ब) 'क्लिक टू कॉल' की सुविधा।
(स) तहसील दिवस/ जनता दरबार का डिजिटीलीकरण।
(द) सांसदों एवं विधायकगणों के लिए 'मुख्यमंत्री संदर्भ'

ई–ऑफिस

'ओपन इण्टरनेट' पर ई–ऑफिस का सरकारी विभागों एवं संस्थाओं में क्रियान्वयन किया गया, जिसमें कुल 418 विभाग/ संस्थायें ऑनबोर्ड की जा चुकी हैं। ई–ऑफिस के माध्यम से दक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं कागज रहित गवर्नेन्स का क्रियान्वयन हो पा रहा है। ई–ऑफिस की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है–

क्रमांक	विवरण	संख्या
1	लाइसेंस की कुल संख्या	15000
2	लाइसेंस आवंटित	11000
3	उत्तराखंड के लिए बनाई गईं ई–रसीदें	13140051
4	उत्तराखंड के लिए बनाई गई कुल ई–फाइलें	163951
ऑनबोर्डिंग स्टैटस		
1	सचिवालय	68
2	प्रबंध–विभाग	42
3	ज़िला	13
4	विभाग	41
5	एजेंसी	4
6	निगम	6
7	संगठन / बोर्ड	10
8	उप–विभागों	226
9	अन्य	8
	कुल	**418**

सचिवालय हेतु 'ई–गेटपास' एवं राजभवन हेतु ई–इन्विटेशन

आई0टी0डी0ए0 द्वारा विकसित कराया गया 'उत्तराखण्ड ई–गेटपास' राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से नागरिकों को राजकीय कार्यालयों / परिसरों में अप्वाइंटमेंट हेतु साधारण डिजिटल प्रक्रिया विकसित की गयी है। इसके अन्तर्गत https://egatepass.uk.gov.in पर आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। उत्तराखण्ड सचिवालय में ई–गेटपास सिस्टम का क्रियान्वयन किया जा चुका है । इस सिस्टम के माध्यम से 1.80 लाख से अधिक ऑनलाईन पास जारी किये जा चुके हैं। राजभवन के लिए निमन्त्रण हेतु ई–इन्विटेशन ऐप्लिकेशन निर्माण कर क्रियान्वयन किया गया है। इसके माध्यम से 15 से अधिक ईवेंट कराए जा चुके है। दूसरे चरण में आई.टी.डी.ए. इस एप्लिकेशन को आगंतुकों के पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड के साथ एकीकृत करने की योजना बना रहा है।

आगामी वर्ष में 'आटीफिशियल इंटेलिजेंस' एवं मशीन लर्निंग आधारित आधुनिक ई–गेटपास सिस्टम सचिवालय प्रवेश के लिए क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। यह सिस्टम प्रचलित सिस्टम से उन्नत है तथा सचिवालय सुरक्षा के लिए अनेक फीचर उपलब्ध करायेगा।

अध्याय 4

क्षमता विकास एवं अनुसंधान कार्य

'ड्रोन' ऐप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र का संचालन

ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (डी0ए0आर0सी0) सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी एवं नेशनल टेक्निकल रिसर्च संस्था (एन0टी0आर0ओ0) भारत सरकार की संयुक्त पहल से वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। इस केन्द्र का उद्देश्य ड्रोन के लिए स्टेट ऑफ आर्ट ड्रोन उपयोग एवं अनुसंधान स्थापित करना, मानव रहित प्रौद्योगिकी की उन्नति और अनुप्रयोग में उत्कृष्ट अनुसंधान का समर्थन, ड्रोन संचालकों हेतु उच्च तकनीकी युक्त प्रशिक्षण व्यवस्था, राज्य के अन्य क्षेत्रो जैसे वन सर्वेक्षण, कृषि इत्यादि के ड्रोन अनुप्रयोगों की क्षमता विकसित करने के लिए तकनीकी सुविधाएं स्थापित करना एवं अन्य विभागों द्वारा आपदा राहत आदि कार्यक्रमों में ड्रोन उपयोग की क्षमता विकसित करने हेतु तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना है।

ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (डी0ए0आर0सी0) के माध्यम निम्नलिखित राज्य / केन्द्र सरकार विभागों के कर्मियों और विभिन्न संस्थानों के छात्रों हेतु 100 से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये एवं माह दिसम्बर 2023 तक 2745 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया –

(1) अर्द्धसैनिक बल यथा बी0एस0एफ0, सी0आर0पी0एफ0, सी0आई0एस0एफ0, आई0टी0बी0पी0।

(2) सिंचाई विभाग, पुलिस दूरसंचार विभाग, एस0डी0आर0एफ0 विभाग, सू0प्रौ0 के अन्तर्गत– स्वान इंजीनियर्स एवं ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर।

(3) आतंकवाद निरोधक दस्ता उत्तर प्रदेश।

(4) बजाज शिक्षण संस्थान से मूक एवं बधिर छात्रों व विभिन्न सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्र।

(5) देहरादून के 30 अग्रणी किसानों जिनमें महिला किसान भी शामिल थी को, कृषि के क्षेत्र में ड्रोन उपयोग के सम्बन्ध में एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (डी0ए0आर0सी0) द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ मिलकर हाल ही में जोशीमठ में भू–धंसाव का ड्रोन सर्वेक्षण किया गया।

इस केन्द्र के माध्यम से ड्रोन संचालन हेतु पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं। विगत वर्ष चमोली आपदा ड्रोन टीम द्वारा क्षतिग्रस्त नेटवर्क सुविधान को ड्रोन के माध्यम से ओ0एफ0सी0 कनेक्टिविटी को पुर्नस्थापित किया गया।

आईटी0 स्किल डेवलपमेंट केन्द्रों एवं कैल्क केन्द्रों का संचालन

माननीय मुख्यमंत्री जी के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ग्रोथ सेन्टर योजना का संचालन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अधीन आई0टी0डी0ए0 द्वारा दो स्थलों यथा– कैल्क केन्द्र (Computer Academy & Learning Centre-CALC) आई0डी0पी0एल0, ऋषिकेश एवं कैल्क केन्द्र पिथौरागढ़ पर आई0टी0 स्किल डेवलपमेंट केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कम्प्यूटर लैब /डिजिटल क्लास रूम तैयार की गयी है।

राज्य में पूर्व से चल रहे हिल्ट्रान कैल्क परियोजना को आई0टी0डी0ए0 को हस्तान्तरित किया जा चुका है, जिसके माध्यम से डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट कोर्सेस संचालित किये जा रहे हैं। **आई0टी0डी0ए0 कैल्क** ने पूरे उत्तराखण्ड में प्रशिक्षण केन्द्रों का एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित किया है, जिसमें प्रशिक्षण उपकरण, शिक्षण संकाय और पाठ्यक्रम (अध्ययन सामग्री), तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए बनाये गये मानदण्डों के अनुसार है वर्तमान में **आई0टी0डी0ए0 कैल्क** के अन्तर्गत 37 कैल्क केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

उत्तराखण्ड राज्य एंव अन्य राज्यों में समाज के सभी वर्गों को कम शुल्क पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से **आई0टी0डी0ए कैल्क** के माध्यम से छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया। आई.टी. उद्योग में वर्तमान प्रचलन के अनुसार परिभाषित पाठ्यक्रम संरचना व अच्छे वातावरण के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में बेसिक, इण्टरमीडिएट ओर उन्नत स्तर के कैरियर उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करता है।

ITDA-CALC द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिए जाने हेतु NCVET (National Council for Vocation Education and Training) जो कि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद (व्यावसायिक शिक्षा में

अल्पकालिक और दीर्घकालिक शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करने और संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी मानकों को डिजाइन करने में लगे संस्थानों की निगरानी के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त, गैर–सांविधिक और नियामक निकाय है।) तथा प्रादेश स्तर पर उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही अंतिम चरणों में है।

स्टार्टअप हब

आई0 टी0 डी0 ए0 द्वारा एस0 टी0 पी0आई0 (Software Technolgy Park of India) के साथ उत्तराखण्ड स्टार्ट अप हब स्थापित किया गया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रदत्त सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न स्टार्टअप इन्कुबेशन केन्द्र न्यूनतम लागत पर स्थापित किये हैं। इसके अन्तर्गत "ड्रोन तकनीकी" हेतु एक उत्कृष्ठ केन्द्र स्थापित होगा।

एमरजिंग तकनीकों के लिए परियोजना प्रबन्धन सेल की स्थापना की जानी प्रस्तावित है, जिससे कि आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग व ब्लौक चेन जैंसी अत्याधुनिक तकनीकों को राज्य की विभिन्न एप्लीकेशन्स में लागू किया जा सके।

अध्याय 5

वित्तीय वर्ष 2023–24 : वित्तीय प्रगति एवं बजट प्रावधान 2024–25

(धनराशि हजार रुपये में)

लेखा शीर्षक/ मानक मद	वित्तीय स्थिति 2023–24		आय–व्ययक
	बजट प्रावधान	स्वीकृत	अनुमान 2024–25
राजस्व			
3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, **60**–अन्य, **600**– अन्य सेवायें			
02–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण/ITDA को अनुदान			
05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	10000	6817	10000
08–पारिश्रमिक	9000	9000	9000
27–व्यावसायिक तथा विषेश सेवाओं के लिए भुगतान	50000	50000	50000
56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	280000	171175	150000
3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, **60**–अन्य, **600**– अन्य सेवायें			
03– क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन			
27–व्यावसायिक तथा विषेश सेवाओं के लिए भुगतान	110000	110000	120000
56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	111500	101664	60000
05– विभिन्न विभागों में होरिजोन्टल कनेक्टिविटी हेतु ITDA को अनुदान			
56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	10000	-	-
योग 3425– राजस्व	**580500**	**448656**	**399000**
पूंजीगत			
4859– दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय **02**–इलेक्ट्रानिक्स **800–अन्य व्यय**			
01 केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
16– राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण/ITDA को अनुदान			
55– पूंजीगत परिसम्पतियों का सृजन हेतु अनुदान	162100	-	1
योग 4859– पूंजीगत	**162100**	**-**	**1**
कुल योग	**742600**	**448656**	**399001**

आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2024–25

विभाग– सूचना प्रौद्योगिकी

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले/बजट		01.04.2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट) वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम) वर्ष 2024–25	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1.	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण	राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल से राज्य में आई0टी0 का सुदृढ़ीकरण।	2190.00	0.01	• सूचना प्रौद्योगिकी भवन का अनुरक्षण एवं संचालन।	• आई.टी. पार्क में आवंटित अतिरिक्त भूमि पर नये भवन किा नर्माण कार्य गतिमान।	• भवन निर्माण कार्य पूर्ण एवं संचालन।	राज्य में समस्त सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं का संचालन कर ई–गवर्नेन्स / गुड गवर्नेन्स तथा नागरिकों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सेवायें प्रदान करना।	एक वर्ष
					• ITDA ढांचे के अन्तर्गत अनुबन्ध / आउटसोर्स पर तैनात कर्मियों का वेतन/ परिलब्धियां – (संख्या 18)	• संशोधित ढांचे के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति/ अनुबन्ध / आउटसोर्स पर तैनात कर्मियों का वेतन/ परिलब्धियां (संख्या 21)	• संशोधित ढांचे के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति/ अनुबन्ध/आउटसोर्स पर तैनात कर्मियों का वेतन /परिलब्धियां(संख्या 42)		
					• मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 का संचालन	• मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 का संचालन	• मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 का संचालन		
					• ड्रोन रिसर्च सेंटर का संचालन एवं ड्रोन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम	• ड्रोन रिसर्च सेंटर का संचालन एवं ड्रोन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम	• ड्रोन रिसर्च सेंटर का संचालन तथा ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण हेतु ड्रोन नीति के अनतर्गत 02 ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना		

					• अपणि सरकार पोर्टल पर अपडेटेड कुल 569 सेवायें लाईव, जिनमें से 394 विकसित / एकीकृत की गयी एवं 175 रि–डायरेक्ट की गयी। • पी0एम0 गतिशक्ति (उन्नति) पोर्टल का क्रियान्वयन, 10 मॉड्यूल के माध्यम से परियोजनाओं की मोनिटरिंग, 767 प्रोजेक्ट्स पंजीकृत।	• अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से 800 सेवायें लाईव। • DBT के अन्तर्गत 10 विभागों की 53 स्कीम लाईव। • पी0एम0 गतिशक्ति (उन्नति) पोर्टल का क्रियान्वयन, 20 मॉड्यूल के माध्यम से परियोजनाओं की मोनिटरिंग, 1000 प्रोजेक्ट्स पंजीकृत।	• सेवाओं के डेवलपमेंट एवं सेवाओं के अनुरक्षण एवं संचालन के लिए के लिए इनहाउस टीम के माध्यम से 1000 सेवायें लाईव एवं DBT के अन्तर्गत 178 स्कीम लाईव। • पी0एम0 गतिशक्ति (उन्नति) पोर्टल का क्रियान्वयन, समस्त 20 मॉड्यूल के माध्यम से परियोजनाओं की मोनिटरिंग एवं समस्त सम्बन्धित प्रोजेक्ट्स पंजीकृत।		
					• स्टेट डाटा सेंटर का संचालन। 85 विभागों की 133 एप्लीकेशन्स होस्टेड थी।	• स्टेट डाटा सेंटर का संचालन अभी तक 93 विभागों की कुल 152 एप्लीकेशन्स होस्टेड।	• समस्त विभागों को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित। • SDC विस्तारीकरण • Disaster Recovery का प्रावधान।		
					• ई–ऑफिस का कियान्वयन सचिवालय, विभिन्न राजकीय विभागों तथा संस्थाओं के 239 कार्यालयों में क्रियान्वयन।	• ई–ऑफिस का 165 विभागों के 450 कार्यालयों में क्रियान्वयन।	• राज्य के समस्त विभागों तथा कार्यालयों में ई–ऑफिस का क्रियान्वयन।		
					–	• Emerging Technology हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल का गठन।	• Emerging Technology Cell के माध्यम से ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत आधुनिक तकनीक का उपयोग।		

2.	क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन तथा विभागों में होरिजोन्टल कनेक्टिविटी	योजना में स्वतंत्र सरकारी नेटवर्क स्थापित कर इसके माध्यम से G2C एवं G2G सेवायें उपलब्ध कराये जाना।	1800.00	-	• ब्लोक/तहसील स्तर तक स्थापित 133 प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स के माध्यम से स्वान नेटवर्क का क्रियान्वयन एवं संचालन • BSNL के अतिरिक्त एयरटेल को वैकल्पिक इण्टरनेट सर्विस प्रोवाईडर का चयन • हॉरिजॉन्टल कार्यालय स्वान से संयोजित–1960 • स्वान नेटवर्क का समस्त जनपदों में अपग्रेडेशन पूर्ण	• 139 प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स के माध्यम से स्वान नेटवर्क का क्रियान्वयन एवं संचालन • बी.एस.एन.एल. एवं एयरटेल के माध्यम से समस्त स्वान केन्द्रों में कनेक्टिविटी संचालित • हॉरिजॉन्टल कार्यालय स्वान से संयोजित–2050	• दो इण्टरनेट सर्विस प्रोवाईडर के माध्यम से कनेक्टिविटी। • फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेस के अन्तर्गत 217 तकनीकी मानव संसाधन के माध्यम से स्वान नेटवर्क के संचालन एवं नेटवर्क का अनुरक्षण। • समस्त विभागों तथा कार्यालयों को हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी प्रदान करना।	स्वान के अन्तर्गत कनेक्टेड राजकीय विभागों/ कार्यालयों/ इकाईयों के ई–शासन कार्य प्रणाली तथा कार्य सम्पादन में वृद्धि।	एक वर्ष
		योग	**3990.00**	**0.01**					

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

क्र. सं.	एस.डी.जी. संकेतक	01.04.2023 को भौतिक स्थिति	31.03.2024 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2024–25	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2024–25	टिप्पणी
1	9c.2. Percentage of Gram Panchayats Covered under Bharat Net भारत नेट **में** शामिल ग्राम पंचायतो का प्रतिशत।	19.43%	25%	-	Rural Communities of the State would gain better access to reliable internet and telecommunications services and they can reap economic growth such as improved connectivity enables rural businesses to participate in the digital economy, opening doors to broader markets and increased revenues.	Data for GPs covered under Bharat Net taken from BBNL site. Additionally, MoU between ITDA and BSNL has been initiated for FTTH Connectivity for 1221 GPs out of which 865 GPs has been covered and rest will be completed upto March 2024.
2	**16.6.1. Number** of government services provided online to citizens नागरिकों को ऑनलाइन प्रदत्त की गई सरकारी सेवाओं की संख्या।	569	800	1000	• Efficiency • Timely delivery (75%) • Processing rate (99%) • Reduce pending rate (1%) • Accountability of officer for services delivery (Right service commission) • Transparency	-
3	16.9.3. Proportion of population covered under Aadhaar (in percentage) आधार के अन्तर्गत शामिल जनसंख्या का अनुपात	100%	100%	100%	Better implementation of various State Government schemes related to Social Development and Direct Benefit Transfer (DBT).	Presently 105.50% Aadhar generated against Projected Population 1,16,37000.00 (as per census 2011) and Actual Aadhar Generated 1,22,77140.00
4	16.6.1. Percentage of functional Common Service Centre (CSC). कुल कियाशील कॉमन सर्विस सैण्टरों का प्रतिशत।	57.43%	61%	70%	• Benefit to the Rural public • All kind of government services and other services under 1 roof @Door Step nearest place • timely delivery and efficiency • Transparency • Reduce pending	March 2023 - registered 22464 Active 12902 31 Dec 2023 Registered 24361 Active 12513 15000